

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 11 मार्च, 2024

विषय: सरकारी विभागों, उपक्रमों एवं निगमों द्वारा धनराशियों को बैंकों में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी विभागों/निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्थानीय निकायों द्वारा शासकीय धन आहरित कर बैंक/पोस्ट ऑफिस खातों में रखा जाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन श्री राज्यपाल द्वारा बनाये गये कोषागार नियम-9 तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-21 व 22बी के अनुरूप नहीं है। फिर भी जिन मामलों में राज्य सरकार की विशिष्ट स्वीकृति से विभागों/निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्थानीय निकायों/संस्थाओं आदि के द्वारा बैंक खाते खोले गये हों/खोले जाने की आवश्यकता अपरिहार्य हो तो उनके सन्दर्भ में निम्नलिखित दिशानिर्देशानुसार अग्रेत्तर वांछित कार्यवाही की जाय:-

1. बैंक खाता खोले जाने हेतु वित्त (व्यय नियंत्रण) विभाग की अनुमति प्राप्त की जायेगी। यदि बैंक खाते वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना खोले गये हैं तो उन्हें तत्काल बन्द करा दिया जाय। यदि उक्त बैंक खाते को बन्द किया जाना कार्यहित में सम्भव न हो तो उक्त बैंक खाते को अग्रेत्तर संचालित किये जाने से पूर्व वित्त (व्यय नियंत्रण) विभाग की अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
2. बैंक में परियोजना अथवा अधिष्ठान सम्बन्धी धनराशि बचत खाते (saving account) में ही जमा की जायेगी तथा किसी भी दशा में चालू खाता (current account) खोला/संचालित नहीं किया जायेगा।
3. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-564/दस-7/97 दिनांक 02.03.1998 के प्रावधानानुसार विभिन्न सरकारी उपक्रमों एवं निगमों द्वारा शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियां (ऋण को छोड़कर) यदि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से बैंकों में जमा की जाती हैं तो उन जमा धनराशियों पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा कराना होगा। उक्त व्यवस्था का भी अनुपालन समस्त विभाग/निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग एवं विभागाध्यक्ष का होगा।
4. निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्थानीय निकायों/संस्थाओं आदि, जो अपने स्वयं की धनराशि से व्यवसाय कर लाभ अर्जित करते हैं और अपने सरप्लस फण्ड का विनियोजन बैंक खातों के माध्यम से करना चाहते हैं, तो केवल इस उद्देश्य के लिये बैंक खाता खोलने हेतु उन्हें वित्त विभाग की पूर्व अनुमति लिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी एवं उपरोक्त प्रस्तर-2 के अनुसार कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित नहीं होगा। अपितु ऐसे निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्थानीय निकायों/संस्थाओं आदि द्वारा अपने नियमों/विनियमों में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार तथा

यथाआवश्यकता अपने निदेशक मण्डल/सक्षम प्राधिकारी के स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर बैंक खाता RBI द्वारा अधिसूचित किसी अधिसूचित बैंक (Sheduled), जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक भी सम्मिलित होंगे, में खाता खोलने की कार्यवाही की जायेगी। ऐसा करते हुए सम्बन्धित संस्थाएँ बैंक में रखी जाने वाली धनराशि की सुरक्षा हेतु भी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

5. उपरोक्तानुसार विभागों/निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्थानीय निकायों/संस्थाओं आदि द्वारा शासकीय धनराशि पर बैंक के बचत खाते में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में दिनांक 31 दिसम्बर तक अर्जित ब्याज को माह जनवरी के पूर्वार्द्ध में IFMS पोर्टल पर "यूकोष" लिंक के माध्यम से राजकोष में जमा करा दिया जायेगा, जिसकी सूचना कैलेंडर वर्ष के बैंक स्टेटमेन्ट तथा ई-चालान की प्रति के साथ शासन के प्रशासकीय विभाग तथा वित्त (व्यय नियंत्रण) विभाग को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष स्तर पर तैनात सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) एवं वित्त सेवा के अधिकारियों (वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी आदि) का होगा।

- 2- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव

Signed by Anand Bardhan
Date: 08-03-2024 11:21:24

संख्या : 197022/XXVII (1)/2024 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 2- निजी सचिव, मा. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), देहरादून।
- 6- महालेखाकार, ऑडिट, देहरादून।
- 7- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 8- आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, पौड़ी/नैनीताल।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10- निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 11- समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 12- समस्त निगम/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय/संस्थाएँ (द्वारा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग)।
- 13- बजट अधिकारी, बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड को उपरोक्त व्यवस्था के पर्यवेक्षण/अनुश्रवण हेतु प्रेषित।
- 14- नोडल अधिकारी, आई.एफ.एम.एस., देहरादून।
- 15- गार्ड फाईल।

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव